भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 230

(जिसका उत्तर सोमवार, 17 मार्च, 2025/26 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया)

प्रारूप डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक की स्थिति

***230. श्री बलवंत बसवंत वानखडेः**

डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का डिजिटल अर्थव्यवस्था में बड़ी कंपनियों के संभावित एकाधिकार और व्यापार की अनुचित रीतियों को रोकने के लिए डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून लाने का प्रस्ताव है;

(ख) प्रस्तावित डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर विचार-विमर्श की वर्ममान स्थिति क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है तथा ऐसे हितधारकों का ब्यौरा क्या है जिनसे परामर्श किया गया हैं;

(ग) क्या सरकार की प्रारूप विधेयक पर और परामर्श के लिए इसे जारी करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं कि प्रस्तावित कानून बड़े डिजिटल प्रतिस्पर्धियों की अत्यधिक प्रभावी स्थिति को विनियमित करने के साथ-साथ नवाचार को बढ़ावा दिए जाने के बीच प्रभावी संतुलन बनाएगा;

(ङ) क्या सरकार ने स्टार्ट-अप सहित छोटे प्रतिस्पर्धियों पर प्रस्तावित 'एक्स-एंटे' ढांचे के संभावित प्रभाव का आकलन किया है तथा किसी भी अनपेक्षित परिणाम को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या यह सही है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यह सिफारिश की है कि डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक के प्रस्तावित मसौदे में एक्स-एंटे प्रावधान को इस चरण पर इस कानून से बाहर रखा जाए; और

(छ) डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए प्रमुख प्रौद्योगिकी फर्मों की समस्याओं का समाधान करने के लिए किन सुरक्षा उपायों/उपायों पर विचार किया जा रहा है?

उत्तर

वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'प्रारूप डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक की स्थिति' के संबंध में दिनांक 17.03.2025 को उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 230 के भाग (क) से (छ) में संदर्भित विवरण

(क) से (ग): "बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार" विषय पर वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अपनी तिरपनवीं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के आधार पर, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (सीडीसीएल) पर एक समिति गठित की।

- मार्च 2023 के दौरान, सीडीसीएल ने उद्योग संघों, घरेलू और विदेशी डिजिटल उद्यमों और थिंक-टैंक आदि सहित प्रस्तावित कानून से प्रभावित होने वाली संस्थाओं और हितधारकों के साथ बंद कमरे में परामर्श किया। हितधारकों की सूची अनुलग्नक-I में दी गई है।

- परामर्श के बाद, सीडीसीएल ने फरवरी 2024 में डिजिटल प्रतिस्पर्धा विधेयक (डीसीबी) के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून (सीडीसीएल) पर समिति की रिपोर्ट और मसौदा डीसीबी को 12 मार्च से 15 मई, 2024 तक ई-परामर्श माध्यम के अंतर्गत एमसीए वेबसाइट पर रखा गया था। कानूनी पेशेवरों, उद्योग संघों, सिविल सोसाइटी संगठनों और भारत में डिजिटल सेवाएं प्रदान करने वाले घरेलू और विदेशी डिजिटल उद्यमों से लेकर 100 से अधिक हितधारकों ने प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत कीं। हितधारकों की सूची अनुलग्नक-II में दी गई है।

- इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 18.06.2024 से 20.06.2024 के बीच हितधारक चर्चाएँ आयोजित कीं।

सभी हितधारकों से प्राप्त सुझावों/इनपुटों/टिप्पणियों की जाँच की जा रही है।

(घ), (ङ) और (छ): सीडीसीएल ने प्रमुख हितधारकों के साथ परामर्श किया और डिजिटल सेवाओं के विनियमन के लिए घरेलू कानूनी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय नियामक प्रथाओं दोनों की जाँच की। इसके पश्चात, मसौदा डीसीबी के निर्माण के दौरान, छोटे व्यवसायों, थिंक टैंकों और प्रमुख तकनीकी फर्मों के व्यापार और उद्योग संघों के कई प्रतिनिधियों के साथ उनके विचार/टिप्पणियाँ लेने के लिए परामर्श किया गया।
सभी हितधारकों से प्राप्त सुझावों/इनपुटों/टिप्पणियों की जांच की जा रही है।

(च) एमईआईटीवाई द्वारा आयोजित हितधारकों की चर्चाओं के अनुसरण में टिप्पणियों/इनपुटों की प्रतीक्षा की जा रही है।

*****

<u>अनुलग्नक- I</u>

1. अमेज़न
2. एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
3. बंडल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और स्विगी
4. सेंटर फॉर द डिजिटल फ्यूचर
5. फ्लिपकार्ट
6. गूगल
7. इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन
8. इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया
9. मेटा **(**फेसबुक**)**
10. ओयो
11. उबर
12. यूएसआईबीसी
13. जोमैटो
14. ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन
15. एलाइंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन
16. अर्थ ग्लोबल
17. एशिया ट्रेवल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री एसोसिएशन
18. एजैडबी और पार्टनर
19. कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स
20. डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन
21. एस्या केंद्र
22. फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया
23. अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद
24. मेकमायट्रिप
25. न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया
26. नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया
27. नैसकॉम
28. पेटीएम
29. ट्विटर

अनुलग्नक- II

क्र.सं.	हितधारक का नाम
1.	नीति आयोग
2.	फर्स्ट भारत
3.	सीसीएओआई
4.	स्विगी
5.	अमेरिकन बार एसोसिएशन
6.	ई-गेमिंग फेडरेशन
7.	यूएस-इंडिया बिजनेस काउंसिल (यूएसआईबीसी)
8.	इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन (आईसीईए)
9.	स्काईस्कैनर
10.	एसोचैम
11.	यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम (यूएसआईएसपीएफ)
12.	मैच ग्रुप
13.	फाउंडर्स एंड इन्वेसटर्स ऑफ इंडियन डिजिटल स्टार्टअप इकोसिस्टम
14.	इंडियन ग्रीवेंस एंड पॉलिसी प्रोजेक्ट (आईजीएपी)
15.	प्ले गेम्स 24*7 प्राइवेट लिमिटेड
16.	नैसकॉम
17.	लूथरा और लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया
18.	टेक फ्रीडम
19.	ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (एआईजीएफ)
20.	इंडियन रेगुलेटरी प्राक्ट्रिस ग्रुप एलएलपी (आईआरपीजी)
21.	मेटा प्लेटफ़ॉर्म इंक
22.	सिविस
23.	शिल्पी भट्टाचार्य, प्रोफेसर, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल (जेजीएलएस)
24.	सेंटर फॉर कम्पटीशन लॉ एंड इकोनॉमिक्स (सीसीएलई)
25.	अमेज़न इंडिया
26.	इंडिया मार्ट
27.	एयरटेल

28.	एक्सेस नॉउ
29.	इंटरनेशनल बार एसोसिएशन (आईबीए)
30.	ब्रॉडबैंड इंडिया फोरम (बीआईएफ)
31.	भारतीय प्रसारण और डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) और भारतीय डिजिटल मीडिया उद्योग फाउंडेशन (आईडीएमआईएफ)
32.	कोएलिशन फॉर अप्प फेयरनेस (सीएएफ)
33.	ओला इलेक्ट्रिक
34.	द डायलाग
35.	इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (आईएफएफ)
36.	इंटरनेशनल सेंटर फॉर लॉ एंड इकोनॉमिक्स
37.	मोशन पिक्चर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (एमपीए)
38.	इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी)
39.	पीआरएस विधायी अनुसंधान
40.	ईबीसी पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड और एससीसी ऑनलाइन
41.	मेकमायट्रिप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
42.	डिजिटल इंडिया फाउंडेशन का गठबंधन (एडीआईएफ)
43.	मैट
44.	टाटा डिजिटल
45.	प्रगतिशील नीति संस्थान (पीपीआई)
46.	फोनपे प्राइवेट लिमिटेड
47.	ट्रिलेगाल
48.	नेटफ्लिक्स
49.	जोमैटो
50.	गूगल
51.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल
52.	नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई)
53.	भारत टेक्नो. संस्थान
54.	इंडस्लाव
55.	डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए)
56.	सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर (एसएफएलसी)

57.	इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई)
58.	हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड
59.	कोन सलाहकार समूह
60.	ईएसवाईए केंद्र
61.	प्रोसस
62.	कट्स इंटरनेशनल
63.	दीपस्ट्रैट प्राइवेट लिमिटेड
64.	फिक्की
65.	इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन (आईटीआईएफ)
66.	(अधिनियम)ऐप एसोसिएशन
67.	अनुपम सांघी एंड एसोसिएट्स (एएसए)
68.	एशिया इंटरनेट गठबंधन (एआईसी)
69.	एशिया यात्रा प्रौद्योगिकी उद्योग संघ (एआईटीआईएए)
70.	कंप्यूटर और कम्युनिकेशन्स इंडस्ट्री एसोसिएशन (सीसीआईए)
71.	इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री (आईएमआई)
72.	माइक्रोसॉफ्ट
73.	कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
74.	डीएमडी अधिवक्ता
75.	ऑल इंडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी (एआईसीएएस)
76.	एकनॉमिस्ट्स एट कंपास लेक्सिकन (जस्टिन कोम्ब्स, कादंबरी प्रसाद, नेहा जोर्गिए) एंड फ़टी कंसल्टिंग (अविनाश मेहरोत्रा, जिनसी फ्रांसिस)
77.	सेंटर फार इंटरनेट एंड सोसाइटी (सीआईएस)
78.	सिद्धार्थ चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर और एसोसिएट डीन, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी
79.	बीटीजी अद्वाया
80.	ऋषभ बेली और आईटी फॉर चेंज
81.	डीएसके कानूनी- अधिवक्ता और सॉलिसिटर
82.	ट्रूकॉलर
83.	डायनामिक कम्पटीशन इनिशिएटिव (डीसीआई)
84.	टचस्टोन पार्टनर्स

85.	इकोनोमिक लॉज प्रैक्टिस (ईएलपी)
86.	डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (डीएससीआई)
87.	उबेर
88.	नबीन जैन
89.	रुचिका गंभीर (शोधकर्ता)
90.	अभिवर्धन (इंडिक पैसिफिक लीगल रिसर्च)
91.	रश्मि बरनवाल (प्रोफेशनल)
92.	अभिषेक मुरुकते
93.	विकास कथूरिया (शोधकर्ता)
94.	जयश्री चंद्रा (प्रोफेशनल)
95.	अमेय कंटक (शोधकर्ता)
96.	इकरा जबीन अंसारी (लिथियम)
97.	पंखुड़ी खंडेलवाल (डायनामिन प्रतियोगिता पहल)
98.	ब्लेज़ फर्नांडिस (भारतीय संगीत उद्योग)
99.	जसलीन कौर (प्रोफेशनल)
100.	मुरुगवेल जानकीरमन (Matrimony.com)
101.	अजय कामत (कामत लीगल)
102.	आकांक्षा जी (शोधकर्ता)
103.	ब्लू भूटानी (दवेस्कों एलएलपी)
104.	विवेक अग्रवाल
105.	एमचम इंडिया
106.	पीपल ग्रुप/Shaadi.com और अन्य